



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 अक्टूबर 2014

सं. टीएमपी/5/2011— वीएसपीएल — महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/5/2011—वीएसपीएल

कोरम:

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितम्बर 2014 के 30वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में बर्थ ईक्यू-8 और ईक्यू-9 में इसके द्वारा प्रहस्तित पोतों के लिए विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. वीएसपीएल का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/5/2011—वीएसपीएल दिनांक 11 अक्टूबर 2011 द्वारा पिछली बार अनुमोदित किया गया था जिसे 22 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च 2014 तक निर्धारित की थी।

2.2. वीएसपीएल ने उक्त आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को हारबर मोबाइल क्रेन के लिए निर्धारित प्रशुल्क की सीमा तक माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अगले आदेशों तक हारबर मोबाइल क्रेन के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ₹ 36.70 प्रति टन की बजाय ₹ 72.75 प्रति टन की पूर्व-संशोधित दर वसूल करने के लिए वीएसपीएल को अनुमति दी थी।

2.3. वीएसपीएल के मौजूदा दरमान (हारबर मोबाइल क्रेन की दर के लिए वैधता के अलावा जो न्यायाधीन हैं) की वैधता कई अवसरों पर विस्तारित की गई है; आखिरी बार विस्तार आदेश दिनांक 4 जुलाई 2014 द्वारा 30 सितम्बर 2014 तक किया गया था।

3. वीएसपीएल ने अपने पत्र दिनांक 10 मार्च 2014 द्वारा एसओआर के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, पिछले आदेश में अनुमोदित एचएमसी की प्रशुल्क मद को ही वीएसपीएल द्वारा चुनौती दी गई है।
4. वीएसपीएल प्रस्ताव दिनांक 10 मार्च 2014 की प्रारंभिक संवीक्षा करने पर, हमारे पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा वीएसपीएल से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से हमारे पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा यह अनुरोध भी किया गया था कि वीएसपीएल के प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण तथा अपनी विशिष्ट टिप्पणियां भेजें। वीएसपीएल और वीपीटी के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।
- 5.1. वीएसपीएल के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 30 सितम्बर 2014 को समाप्त हो गई थी। उपर्युक्त पैरा 4 में बताई गई स्थिति के मद्देनजर, अंतिम रूप से विचार करने के लिए इस मामले को तैयार करने में समय लगेगा। अतः, यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान (हारबर मोबाइल क्रेन की दर के लिए वैधता के अलावा जो न्यायाधीन है) की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 31 दिसम्बर 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
- 5.2. यदि स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2014 के बाद दिखाई देता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन -III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27 October 2014

No. TAMP/5/2011- VSPL.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Vizag Seaport Private Limited as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/5/2011- VSPL

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 30th day of September 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Private Limited (VSPL) for the vessels handled by it at berth EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust.

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of VSPL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/5/2011-VSPL dated 11 October 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 November 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2014.

2.2. The VSPL has challenged the said Order dated 11 October 2011 in the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh to the extent of the tariff fixed for the Harbour Mobile Crane. The Hon'ble High Court has permitted the VSPL to levy the pre-revised rate of ₹ 72.75 per tonne instead of ₹ 36.70 per tonne approved by this Authority for the Harbour Mobile Crane until further orders.

2.3. The validity of the existing SOR (except the validity for the rate of Harbour Mobile Crane which is subjudice), of the VSPL has been extended on couple of occasions; the last extension being till 30 September 2014 *vide* Order dated 4 July 2014.

3 The VSPL has on its own filed the proposal for revision of the SOR *vide* its letter dated 10 March 2014. As stated above, only tariff item of HMC approved in the last Order is challenged by VSPL.

4. On a preliminary scrutiny of the VSPL proposal dated 10 March 2014, additional information/ clarifications has been sought from VSPL *vide* our letter dated 29 September 2014. The Visakhapatnam Port Trust (VPT) has also been requested *vide* our letter dated 29 September 2014 to furnish its specific comments and additional information/clarifications on some of the points with reference to the proposal of the VSPL. The response of VSPL and VPT is awaited.

5.1. The extended validity of the existing SOR of VSPL expired on 30 September 2014. In view of the position brought out in para 4 above, it will take time for this case to mature for final consideration. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR, (except the validity for the rate of Harbour Mobile Crane which is subjudice), from the date of its expiry till 31 December 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5.2. If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2014]